रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

कम लागत में रसायनशास्त्र एवं फार्मेसी विभाग मे सेनेटाइजर एवं डिसइन्फेक्टेन्ट का निर्माण

विश्वविद्यालय को आत्म निर्भर बनाने का अभिनव प्रयास–कुलपति प्रो. मिश्र

जबलपुर 21 अगस्त। वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण को देखते हुये विश्वविद्यालय के रसायनशास्त्र एवं फार्मेसी विभाग की प्रयोगशाला में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का अनुसरण करते हुये कम लागत में हैण्ड सेनेटाइजर एवं सरफेस डिसइन्फेक्टेन्ट का निर्माण किया गया है। ये सेनेटाइजर एवं डिसइन्फेक्टेन्ट सतह एवं त्वचा मे उपस्थित सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों जैसे–जीवाणु, फफूंद, कोरोना एवं अन्य वायरस, प्रोटोजोआ आदि को नष्ट करने में सक्षम हैं।

माननीय कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र ने विभाग की इस सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय को सेनेटाइजर निर्माण के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने का अभिनव प्रयास है। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि उक्त सामग्री का निर्माण लगातार किया जाये जिससे भविष्य में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके एवं विश्वविद्लाय के प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहें।

प्रभारी कुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्रा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार की तुलना में कम लागत में सेनेटाइजर का निर्माण महत्वपूर्ण एवं लोक–कल्याणकारी कदम है। उन्होंने बताया कि अभी फार्मेसी विभाग द्वारा कुछ विभागों में इस सेनेटाइजर को उपलब्ध कराया गया है तथा इसे शीघ्र ही विश्वविद्यालय के सभी विभागों के लिए भी उपलब्ध कराया जायेगा।

विभागाध्यक्ष प्रो. आर.पी. मिश्र ने बताया कि माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से हैण्ड सेनेटाइजर एवं सरफेस डिसइन्फेक्टेन्ट के निर्माण कार्य में विभाग के डॉ. प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, मो. वाशिद खान, डॉ. दीपक रजक, श्री पुष्पेन्द्र सिंह जगेत, रीतेश चौरसिया, चंदन सिंह अहिरवार, अभिषेक पाण्डेय, भावेश पटेल एवं लैब. सहायकों का सहयोग रहा है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तय समय सीमा पर क्रियान्वयन है जरूरी–कुलपति प्रो. मिश्र

रादुविवि में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: क्रियान्वयन की रूपरेखा' विषय ऑनलाईन परिचर्चा का आयोजन

जबलपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय समय सीमा में नीति को लागू करने की सिफारिश की गई है। यदि इन बदलावों के सही परिमाण चाहिए, तो इन्हें एक समयसीमा में लागू करना होगा। प्राचीन ज्ञान परंपरा को किनारे रखकर भारत एक राष्ट्र के रूप में सबल नहीं हो सकता है। ये पहली बार है कि शिक्षा नीति को व्यापक परामर्श से तैयार कर बनाया गया है। इसमें खामियां हो सकती है, लेकिन जितने भी सुझाव आए थे, उनको मंथन का हिस्सा बनाया गया है। उपरोक्त विचार माननीय कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय में आयोजित ऑनलाईन परिचर्चा के दौरान व्यक्त किए।

माननीय कुलपति प्रो. मिश्र ने कहा कि कोविड के दौर में जो आर्थिक संकट नजर आ रहा है, उसकी एक वजह है लोगों में स्व–रोजगार की भावना और उसके प्रति सम्मान की कमी। नई शिक्षा नीति इसी को दूर करेगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के तत्वावधान में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: क्रियान्वयन की रूपरेखा' विषय पर आयोजित परिचर्चा में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता राष्ट्रीय चिंतक एवं विचारक आचार्य अरूण दिवाकर नाथ बाजपेयी, पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टाईम लाईन की बात सबसे महत्वपूर्ण है। इसको लेकर जल्दी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं है। अभी समय है और इसमें मौजूद विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हर साल नीति के अमल की समीक्षा भी की जाएगी। इसके साथ ही तय रोडमैप के तहत जब पूरी नीति 2035 तक लागू हो जाएगा, तो इसकी एक व्यापक समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही नीति पर ठीक तरीके से अमल हो रहा है, इस पर भी नीति के लागू होने के अगले दस सालों तक नजर रखी जाएगी। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक बिन्दु पर सांख्यिकी आंकड़े तैयार करना महत्वपूर्ण है।

देश की शिक्षा व्यवस्था होगी तय–

रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आईक्यूएसी समन्वयक एवं ऑनलाईन परिचर्चा संचालक आचार्य अंजना शर्मा ने बताया कि देश की शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा और दिशा तय करती है। नई पॉलिसी में उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमिशन करेगा। इन संस्थाओं के अलग–अलग विभागों के लिए नियम, कानून और गाइड लाइन तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। इस अवसर पर आयोजन समिति के आचार्य कमलेश मिश्र, आचार्य सुवेन्द्र नाथ बागची, आचार्य रविन्द्र कुमार यादव, आचार्य शैलेष चौबे, आचार्य सुधाकर नाथ मिश्र, डॉ. लोकेश श्रीवास्तव, डॉ. विशाल ओमप्रकाश बन्ने, डॉ. अजय कुमार गुप्ता, डॉ. राम कुमार गुप्ता सहित सभी प्राध्यापक एवं अतिथि विद्वान मौजूद रहे।

विशिष्ट वक्ताओं ने रखे ये विचार –

आचार्य सरदूल सिंह संधु, कार्यपरिषद सदस्य ने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों को अभी से सक्रिय होना पड़ेगा। तभी इस शिक्षा नीति में शामिल लक्ष्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ हासिल किया जा सकता है। इसमें 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगें। वहीं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। इसके लिए अभी से तैयारियां प्रारंभ करनी होगी।

आचार्य ममता राव, कार्यपरिषद सदस्य ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के लिए बच्चों को अधिक से अधिक प्रोत्याहित करने पर जोर दिया गया है। विधि क्षेत्र में इस पॉलिसी में बार काउंसिल की प्रमुख भूमिका बताई गई है। सामाजिक न्याय से लेकर मानवाधिकारों तक की बात करने वाली इस पॉलिसी के अनुसार शिक्षण संस्थानों को रूपरेखा के अनुसार कार्य करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय को अभी से विधि पाठ्यक्रमों को नए स्वरूप के अनुसार ढालने की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए।

आचार्य राकेश बाजपेयी, संकायाध्यक्ष विज्ञान ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले इसका नियमन करना जरूरी है। चूंकि इसके लिए हमें अपने वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य को 360 डिग्री के कोण पर परिवर्तित करना है, इसलिए नई पॉलिसी के अनुरूप विधान तैयार करना सबसे अधिक आवश्यक है। इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में भी व्यापक बदलाव करने होंगे। पॉलिसी में मौजूद बॉडीज को जल्द से जल्द क्रियाशील करना होगा।

आचार्य धीरेन्द्र पाठक, संकायाध्यक्ष कला ने कहा कि नई शिक्षा नीति आने में जितना वक्त लगा, उसके क्रियान्वयन में संभवतः उतनी देरी न हो। इसे लेकर एक विस्तृत रोडमैप आवश्यक है। जिसके तहत 2024 तक नीति के ज्यादातर प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें उल्लेखित कई बिन्दुओं को इसी साल लागू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए सभी को मिलकर तैयार होना है। सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षकों की जरूरत है, जिसपर ध्यान देना चाहिए।

आचार्य रामशंकर, विभागाध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग ने कहा कि नई शिक्षा नीति दरअसल एक पॉलिसी डाक्यूमेंट है, जिसमें सरकार का शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में विजन क्या है बताया गया है। यह नीति तब तक फलीभूत नहीं होगी जब तक इसका सही क्रियान्वयन नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज की परिकल्पना यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की है यह एक दिन में नहीं होती बल्कि इसमें लम्बा समय लगता है।

रादुविवि जनसम्पर्क प्रकोष्ठ / क्रमांक / 925 / 21.08.2020